परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू किया गया है। जिसमें निम्नांकित घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वयन होंगे:- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व-रोजगार कार्यक्रम 4. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 8. सूचना संप्रेषण मद	250000	**1.** स्वयं सहायता समूह का गठन-2556 (प्रति समूह 10-15 सदस्य), स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्ती निधि-3000, एरिया लेवल फेडरेशन का गठन-100, एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्ती निधि-100, टाऊन लेवल फेडरेशन का गठन-5, वित्तीय समावेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम-100 **2.** कौशल उन्नयन हेतु विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण -10000 **3.** व्यक्तिगत ऋण प्रकरण-4000, समूह ऋण-300, स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण-2000 **4.** विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर पर-06/ शहर स्तर पर-75, सामु संगठक-208 **5.** पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन हेतु सर्वे-109, वेण्डरों को परिचय पत्र वितरण-18000, वेंडिग प्लान का चिन्हांकन एवं निर्माण-15, शहरी पथ विक्रेताओं हेतु प्रशिक्षण-6000 **6.** नवीन आश्रय स्थल निर्माण-5, नवीन आश्रय स्थल हेतु सामग्री क्रय-03, आश्रय स्थलों के संचालन रख-रखाव -20 **7.** प्रशासकीय व्यय हेतु **8.** उत्कृष्ट कार्यो के विडियों फिल्म निर्माण एवं अन्य प्रचार-प्रसार	
2	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	स्मार्ट सिटीमिशन के दृष्टिकोण में इसका उद्देय उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो	40000		

परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते है, एक स्वच्छ और सुस्थित वातावरण प्रदान करते है और स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवरंचना घटक निम्नानुसार हैः- 1. पर्याप्त जलपूर्ति 2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति 3. ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सहित साफ-सफाई 4. सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन 5. विशेषतः गरीबों के लिए किफायती आवास 6. सक्षम आई.टी. कनेक्टीविटी और डिजीटेलाईजेशन 7. सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेस और नागरिक भागीदारी 8. सुस्थिर पर्यावरण 9. विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा 10. स्वास्थ्य और शिक्षा		रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि. अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 927.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें लगभग रू. 404.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी प्रकार राशि रू. 523.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है ।	
3	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	स्मार्ट सिटीमिशन के दृष्टिकोण में इसका उद्देय उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते है, एक स्वच्छ और सुस्थित वातावरण प्रदान करते है और स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवरंचना घटक	40000		

परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		निम्नानुसार हैः- 1. पर्याप्त जलपूर्ति 2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति 3. ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन सहित साफ-सफाई 4. सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन 5. विशेषतः गरीबों के लिए किफायती आवास 6. सक्षम आई.टी. कनेक्टीविटी और डिजीटेलाईजेशन 7. सुशासन, विशेषतः ई-गवर्नेस और नागरिक भागीदारी 8. सुस्थिर पर्यावरण 9. विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा 10. स्वास्थ्य और शिक्षा		बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमि. अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 783.00 करोड़ का एससीपी फंड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें लगभग रू. 88.00 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी प्रकार राशि रू. 695.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर है ।	
4	स्वच्छ भारत अभियान	यह केन्द्र प्रवर्तित है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार के स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित 05 घटक में योजना क्रियान्वयन होंगेः- 1. सार्वजनिक शौचालय 2. निजी/व्यक्तिगत शौचालय 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 4. सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण 5. कैपेसिटी बिल्डिंग/प्रशासनिक व्यय कये जाने हेतु	1500000	भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत निम्न घटक निर्धारित किए गये हैः- **1.** आईएचएचएल/सीटीपीटी, एस्पीरेशनल टॉयलेट **2.** यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट **3.** सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट **4.** आईईसी एवं ंबिहेवियर चेंज **5.** केपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट	

परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
				स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा एक्शन प्लान तैयार कर राज्य से सक्षम स्वीकृति उपरांत भारत सरकार को अंतिम स्वीकृति एवं राशि जारी करने हेतु एक्शन प्लान प्रेषित किए गये हैं।	
5	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लिये क्रियान्वयन होंगे:- 1. झुग्गी बस्ती पुर्नविकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण	10200000	प्रधानमंत्री आवास योजना की मिशन अवधि भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2024 तक बढ़ा दी गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीएलसी घटक अंतर्गत 62500 आवास (प्रगतिरत एवं अप्रारंभ) तथा एचपी घटक अंतर्गत 18700 आवास (प्रगतिरत एवं अप्रारंभ) को पूर्ण कराया जाना है। भारत सरकार द्वारा ईबीआर मद की राशि सीधे सूडा के खाते में तथा नॉन-ईबीआर मद की राशि राजकीय कोषालय में हस्तान्तरित की जाती है। अतः नॉन-ईबीआर मद के लिए प्रावधानित राशि की आवश्यकता होगी।	
6	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्को और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके	5000000		

परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		शहरों की भव्यता बढ़ाना ।		प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
7	मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना	आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से एमबीबीएस डॉक्टर की टीम द्वारा मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान करना।	3000000	प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
8	शहरी क्षेत्रों में गौठान निर्माण	योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के गोधन (पालतू और आवारा) के रख-रखाव हेतु पारंपरिक एवं प्रचलित व्यवस्था को बनाये रखना है।	100000	प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
9	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार आदिवासी उपक्षेत्र, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं सामान्य क्षेत्रों के निकायों को पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविघाओं लिए अनुदान	900000	170 नगरीय निकायों के लिए निम्नाकिंत कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. पुल/पुलिया निर्माण	
11	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना	नदियों के किनारे स्थित नगरीय निकायों में सवीरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर जल प्रदूषण से मुक्त किया जाना है।	300000	प्रदेश के 06 नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। 15000 लाभान्वित होंगे ।	
11	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	10000000		

परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
				प्रदेश की 170 स्थानीय निकायों में अधोसरचना विकासा अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं :- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड् निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. पुल/पुलिया निर्माण।	
12	नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	नगरीय निकायों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर टेंकर मुक्त कराया जाना है ।	2550000	प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
13	मुख्यमंत्री मितान योजना	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक शासकीय कार्य सुनियोजित तरीके से संचालित हों और राज्य के नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।	100000	प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।	
14	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित कराना	1350	जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाएगें, जिसमें लगभग 4150 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15000 लाभान्वित होंगे ।	